भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 217

उत्तर देने की तारीख 21 जुलाई, 2025

सोमवार, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

निजी और सरकारी क्षेत्र में आईटीआई का आधुनिकीकरण

217. डॉ. सी. एम. रमेशः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निजी और सरकारी क्षेत्रों में विशेषकर आंध्र प्रदेश के संबंध में, अनुमोदित 60,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय योजना सहित, कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का आधुनिकीकरण किया जाएगा;

(ख) उक्त पहल के तहत शुरू किए जाने वाले नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में संबंधित उद्योग जगत से कोई परामर्श लिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) देश भर में कुल एक हज़ार (1,000) राजकीय आईटीआई को हब-एंड-स्पोक मॉडल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कोई आबंटन नहीं किया गया है।

(ख) अनुमोदित योजना उद्योग साझेदारों को मौजूदा पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करने तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रम शुरू करने और नियोज्यता में सुधार करने हेतु लचीलापन प्रदान करती है।

(ग) जी हाँ।

(घ) उद्योग संघों और प्रमुख उद्योगपतियों के साथ परामर्श किया गया है। इनमें भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन परिसंघ (क्रेडाई), भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी (सियाम), भारतीय स्टाफिंग महासंघ, तिरुपुर निर्यातक संघ और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह जैसे संगठन शामिल हैं। जिन प्रमुख कंपनियों से परामर्श किया गया उनमें मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू लिमिटेड, टाटा समूह, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, अडानी समूह, जे एंड के सीमेंट्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सैमसंग और प्रमुख दवा कंपनियाँ शामिल हैं।

*****